

15.05 hrs.

RESOLUTION RE STEPS TO IMPROVE ECONOMY AND TO REDUCE INEQUALITIES OF INCOME, ETC.—*contd.*

MR DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further consideration of the resolution moved by Shri Kanwar Lal Gupta on the 9th December, 1977.

Shri Gupta.

श्री कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव कि पी पार्टी का प्रस्ताव नहीं है, मेरा वह प्रस्ताव किसी दल का प्रस्ताव नहीं है। यह राष्ट्र की जो सब से बड़ी समस्या है वह सुलझाई जा सकती है यदि सभी लोग मिल कर के काम करें। मैं समझता हूँ इस प्रस्ताव में जहाँ मेरी पार्टी साथ देगी वहाँ विरोध पक्ष के लोग भी इससे सहमत होंगे। इस सदन का शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जो इसका विरोध करेगा या इससे अपना मतभेद रखेगा। प्रापको याद होगा सितंबर, 1963 में डा० लोहिया ने इस सदन में यह सवाल उठाया था जब उन्होंने कहा था कि भारत के 21 करोड़ लोगों की रोजाना आय तीन आने है। उस समय के प्रधान मंत्री जो थे उन्होंने कहा था कि यह आंकड़े गलत हैं और योजना मंत्री ने दूसरे आंकड़े बताये थे लेकिन डा० लोहिया ने अपने तथ्यों और आंकड़ों द्वारा सिद्ध कर दिया था कि भारत की 40 परसेंट आबादी की औसत आय तीन आना रोज है। डा० लोहिया ने वह प्रस्ताव रख करके इस देश की बहुत बड़ी सेवा की थी। मैं इस सदन और देश की तरफ से उन्होंने जो ऐसा प्रस्ताव रखा था, उन के आदर में अपना सिर नतमस्तक करता हूँ क्योंकि उन्होंने भारत की ऐसी जनता की आवाज यहाँ पर उठाई थी जो कि बाहर नहीं बोलती। उन्होंने

ऐसे लोगों की आवाज उठाई थी जिनकी आबखार में चर्चा नहीं होती। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश में लगभग बीस करोड़ लोग ऐसे हैं, 62 करोड़ लोगों में से, जिनकी आय 25 पैसा रोजाना से ज्यादा नहीं है। कोई आबखार, कोई धर्यशास्त्री, कोई एकोनामिस्ट, कोई सरकार और कोई दल उनकी बात के बारे में चर्चा नहीं करता। जनरल बाते होती हैं कि खेती का उत्पादन बढ़ना चाहिए, इण्डस्ट्रीज का उत्पादन बढ़ना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का भत्ता बढ़ना चाहिए, मजदूरों का भत्ता बढ़ना चाहिए—मैं उस के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन ऐसे लोग भी तो इस देश में हैं जो आर्गनाइज्ड लेबर नहीं हैं, किसी यूनियन के बन्बर नहीं हैं, जो फार्मर भी नहीं हैं, जो मकानबेंट सर्विस में भी नहीं हैं, जो व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं हैं तो उन लोगों की आवाज को कौन उठायेश ? आज हमारे देश में चारों तरफ रेत या रेगिस्तान है और कहीं कहीं पर देश में आईलैंड दिखाई देते हैं यह बरिबी का रेगिस्तान है लेकिन बीच में कहीं आईलैंड दिखाई देते हैं। प्राप प्रशोका होटल में जाय, प्राप ओबेराय में जाय या शहरों में जहाँ कच्चे माने होते हैं वहाँ पर प्राप जाय तो प्राप को थोड़ा थोड़ा दिखाई देना कि वह देश भी बहुत सम्पन्न हो गया है लेकिन अगर प्राप बिहार में जायें, कबायली इलाकों में जायें, मिजोरम और नागालैंड में जायें या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जायें तो देखेंगे कि लगातार तीस साल की आजादी के बाद भी जब कि उसकी बागडीर हमारे हाथ में है, उसकी किस्मत बनाने वाली हम हैं फिर भी महिस्तायें आज नहीं करती हैं। आज भी उन को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती। आज भी लोग शोबर से अपना खुन चुम कर खाते हैं और पहनने के लिए उन के पास कपड़ा नहीं है। रहने के लिए भकाम का तो सवास ही पैदा

श्री कंवर लाल गुप्त]

पैदा नहीं होता । तो ऐसे बीस करोड़ लोगों की धावाज कौन उठायेगा ?

15.07 hrs.

[SRI DHIRENDRANATH BASU in the Chair]

इस देश के विधान ने प्रजातंत्र दिया है, पोलिटिकल इक्वैलिटी भी दे दी है कि हर भ्रादमी का एक वोट है चाहे वह प्रधान मंत्री हों, टाटा-बिड़ला हों या कोई गरीब भ्रादमी हो जो कि झोंपड़ी में रहता है—हर एक का समान वोट होगा । लेकिन क्या पोलिटिकल इक्वैलिटी से देश की समस्याएँ हल हो जायंगी, क्या पोलिटिकल इक्वैलिटी से देश के भ्रन्दर प्रजातन्त्र रह सकता है ? जब तक गरीबी और भूखमरी रहेगी, पेट में भ्रग जलती रहेगी, देश के भ्रन्दर भ्रग बुझ नहीं सकती है, देश में भी जलती रहेगी, उस को कोई रोक नहीं सकता । पोलिटिकल स्टेबिलिटी लानी सानी है तो भ्राप को इकोनामिक-इक्वैलिटी भी लानी होगी । जब तक भ्राधिक व्यवस्था ऐसी नहीं होती, तब तक इकोनामिक इक्वैलिटी नहीं भ्राती, तब तक प्रजातंत्र नहीं रह सकता, उस के लिये हमेशा खतरा बना रहेगा ।

भ्राज हड़तालें हो रही हैं, तरह-तरह की मांगें हो रही हैं । मैं हड़तालों के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो भूखा है, वह क्या नहीं करेगा । तुलसीदास जी ने कहा है—खाली पेट भ्रजन भी नहीं हो सकता है, खाली पेटवाले के लिये कोई भ्रगवान नहीं है । स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा है—यदि भ्रगवान को याद करना है, तो पेट भ्रग हुआ होना चाहिये । भ्रगर प्रजातंत्र रखना है तो लोगों को खाना मिलना चाहिये, एसेसियल-कम्युडिटीज मिलनी

चाहिये । भ्राज भेरा सदन के सामने भ्रर सरकार के सामने यह सवाल है कि क्या उन बीस करोड़ लोगों के लिये भ्राप इस बात की गारन्टी दे सकते हैं कि चार साल या पांच साल तक जो भ्राप की भ्रवधि है, उस भ्रवधि में उन को भ्राप भ्रावश्यक वस्तुयें देंगे ? यदि भ्राप देंगे, तो क्या देंगे, कैसे देंगे?

भ्राप कहते हैं कि हम ने पीने के पानी के लिये 40 करोड़ रुपये का प्राविजन किया है, सड़कों के लिये पर्याप्त धन रखा है, राशन की दुकानें खोल दीं, लेकिन जिस चीज की मैं बात करता हूँ, जिन लोगों के लिये मैं भ्राज बोल रहा हूँ—वहां राशन की दुकानें नहीं हैं, वहां सड़कें नहीं बनती हैं, वहां पीने का पानी भी नहीं है । सभ्रापति महोदय, राशन सिस्टम में 50 करोड़ रुपये की सबसिडी सरकार हर साल देती है, फर्टिलाइजर के लिए 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, इलैक्ट्रिसिटी में सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान होता है, इसी तरह जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको सैकड़ों करोड़ रुपए का इन्सेन्टिव देते हैं । सब मिला कर उड़ें या दो हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी इन्सेन्टिव और लास सरकार बरदाश्त करती है । लेकिन इसका लाभ किसको होता है ? इसका लाभ ऊपर के कुछ लोगों को होता है । जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा किसान है—ये सब लाभ इन लोगों को होता है, उन 20 करोड़ पिछड़े इन्सानों को नहीं होता है, इसलिए कि उनकी ध्रावाज खुलती नहीं है, वे भ्रपना पेट मसोस करदम तोड़ देते हैं । भ्रखबारों में भी उनकी चर्चा नहीं होती, वे भूख से मर गए या किसी बीमारी में मर गए—किसी को पता नहीं चलता ।

मैं इस सवाल में किसी तरह की पोलिटिकस को नहीं लाना चाहता । मैं यह

मानता हूँ कि यह सरकार जो केवल 9 महीने पहले बनी है, आज उस का जवाब नहीं दे सकती। जिस पार्टी ने 30 साल तक यहां लगातार राज्य किया, शायद दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ, जहां बगैर किसी बाधा के तीस साल तक किसी ने राज्य किया हो, केवल इसी पार्टी ने इस देश में राज्य किया, लेकिन पिछले तीस सालों का उसका पिछला इतिहास यह है कि बीस करोड़ ग्रामियों की ग्रामदानी केवल 25 पैसे रोज है। मैं आप से जवाब नहीं मांगता, लेकिन मैं यह जरूर मांगता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया, वह आप के सामने है, लेकिन अब आप क्या करना चाहते हैं? आप पांच सालों में क्या क्या योजनाएँ लायेंगे। इन लोगों के लिए सड़क, पानी, कपड़ा उपलब्ध करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि ये सब चीजें उन लोगों के लिए नहीं हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके लिए आपने कोई चीज बनाई है क्या? मेरे पास आंकड़े हैं जो सरकार ने दिए हैं। एक तरफ तो यह चीज है और दूसरी तरफ बिग बिजिनेस हाउसिस हैं जिनके बारे में मंत्री महोदय ने परसों तरसों ही सदन में जवाब दिया है। इनके एसेट्स को आप देखें कि 1951 में जो ये थे उनके मुकाबले में आज कितने हो गए हैं।

The figure was Rs. 594 crores in 1951. It went up to Rs. 2759 crores in 1971 and to Rs. 3717 crores in 1975-76.

1951 से ले कर 1975 तक 24-25 साल में सात गुना उनके एसेट्स बढ़ गए हैं। जब पहले डा० लोहिया ने इन लोगों का सवाल उठाया था अगर परचेजिंग कंपनी का हिसाब लगाया जाए तो पहले से अब उनकी यह कम हो गई है। मेरा सुझाव है कि आप भ्रमण से सैस या टैक्स या सरचार्ज हर एक पर लगा दें। जो बड़ा फार्मर है, बड़ा सलेरी

क्लास का ग्रामदानी है, ट्रेडर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिस किसी की एक हजार या पांच सौ रुपए से ऊपर ग्रामदानी है उस पर आप स्पेशल टैक्स लगा सकते हैं और इस तरह से आप एक साल में एक हजार करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। थोड़ी बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स हीयर एंड थेयर बुड नाट डू। एक ग्रामदानी जो एक या दो कारें रखता है उसकी हर कार के पीछे लगाएं, जो भी लजरी ग्राइंटम्स हैं उनकी परिभाषा भी उनके हिसाब से आपको देखनी होगी, जो मोटर साइक्स रखता है, एयर कंडीशनर रखता है, कूलर रखता है, फीजर रखता है उन सब पर आप इस टैक्स को लगाएं। एक हजार करोड़ रुपया साल का इस तरह से आप इकट्ठा करें और यह राशि आप इन लोगों की बहबूदी के लिए लगाएं। एक भ्रमण से इसकी योजना बननी चाहिए। और उस इलाके में यह खर्च होनी चाहिए। ऐसा आप ने किया तभी कुछ हो सकेगा। जैसे पहले सरकार कहानियां बनाया करती थी वही कहानियां आप भी बनाते हैं, ऐसा कहा जाएगा। आप कभी यही कह देंगे कि हमने पानी इतना कर दिया है, सड़कें इतनी बना दी हैं, सबसिडी दे दी है और इससे कुछ नहीं होगा। स्पेशल टैक्स और इन लोगों के लिए हों। जब आप जवाब दें तो इस का उत्तर आप मुझे भ्रमण दें कि आप यह टैक्स लगायेंगे या नहीं। हर एक पर यह लगना चाहिये ताकि पांच साल में आप को पांच हजार करोड़ मिल जाएं जो कि इन लोगों पर खर्च हों। इस से उन का लेबल कुछ ऊपर आ सकेगा। आज कोई लेबल ही नहीं है।

हम पांच योजनाएं बना चुके हैं। इनका असर क्या हुआ है। चार योजनाओं में हम पच्चीस हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। इतना खर्च करने के बाद भी क्या लाभ हुआ है? इसकी इको-

[श्री शंकर साह गुप्त]

नोमिन्स को प्राप्त देख तो आपको पता चलना कि जो गरीब था वह और गरीब हो गया है और जो धनी था वह और धनी हो गया है (व्यवधान)।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो पंचवर्षीय योजनायें बनीं उन से मैं यह नहीं कहता कि देश को लाभ नहीं हुआ। देश प्राण बढ़ा है, उद्योग और खती बढ़ी है। लेकिन इन 20 करोड़ लोगों का क्या हुआ, इनके केश में कोई प्रगति हुई क्या? मैं कहता हूँ कि नहीं हुई, और अगर हुई भी तो बहुत मामूली। और इससे यह नतीजा निकला कि गरीब गरीब होता गया और धनी धनी होता गया। अब यह डिसपरिटी हो गई। डिसपरिटी से इरीण्ड्स पैदा होंगे, अयलेंस होनी और फिर कलेश होगा और एक ऐसी हालत आजायेगी जो देश में प्रजातंत्र खतरे में पड़ जायगा। मैं समझता हूँ कि जो रोलिंग प्लान बनाने की योजना है वह एक अच्छा आईडिया है ताकि हर साल उस पर विचार किया जा सके कहां तक हम आगे गये हैं, किस क्षेत्र में आगे गये हैं, और किस में हमें आगे जाना है और उसके बाद दोबारा उस पर रीअसेसमेंट हो जाय। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो तरीका चला रहा है प्लान बनाने का वह ज्यादा तस्ली-बन्ध नहीं रहा। तो यह सारी समस्याएँ हैं। अब इस का समाधान क्या होगा? एक तरफ तो भूखा भ्राम्ही है और दूसरी तरफ यह है कि जो धनी भ्राम्ही है वह धनी धनी की नुमाइश करता है। उससे गरीब को और ज्यादा पिच होता है। तो मैंने इसमें यह भी कहा है कि जो खर्चा हो उस पर भी सीलिंग लगनी चाहिये। आप को सभापति जी, मालुम होगा कि उधर

कानपुर में मिल के मजदूरों पर गोली चली 10, 12 लोग मारे गये और उखी मिल मालिक के यहां दिल्ली में शादी हो रही थी। वहां पर 7, 8 लाख रु० खर्च किया गया। मेरी ज्यादा उम्र नहीं है, माननीय श्री शंकर मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन पहले कितने भी लोग धनी हों लेकिन धनी होने के बाद भी उन के रहन सहन से यह पता नहीं लग सकता था कि कौन धनी है कौन गरीब है, वह अपने पैसे की नुमाइश नहीं करते थे। मैंने पहले भी बताया था कि मैं सुबह सैर करने जाता हूँ, सभापति जी, हमारे पड़ोस में 5, 7 मकान छोड़ कर एक भ्राम्ही रहते हैं, उन की कोठी है, माननीय तिवारी जी जानते होंगे, उन के 7, 8 कुत्ते जोड़ जाते हैं, चार नौकर रख हुए हैं और उन कत्तों पर उनका कम से कम 2, 3 हजार रु० महीना खर्च होता है। अब आप बताइये कि एक तरफ तो यह नुमाइश है इसको खत्म होना चाहिये और सरकार को उस दिशा में कदम उठाना चाहिये। पहले आपने एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया था लेकिन उनका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। तो मैं यह चाहता हूँ कि सरकार इस चीज के ऊपर रोक लगाये। किस तरह से हो मेरे ध्यान में कोई तजवीज नहीं है, कोई कानक्रीट प्रॉपोजल नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि इस के बारे में विचार किया जाये कि कोई भी भ्राम्ही अपनी रिच नैस और पैसे की एग्जीबिशन न कर पाये। इस के लिये सरकार को कोई योजना अवश्य ही बनानी चाहिये ताकि गरीब के दिल में पिच तो न हो कि मैं भ्राम्ही भी हूँ और मेरी बड़ज्जती चौराहे पर हो रही है।

सभापति महोदय, हमारे देश में 20 हजार लोग रोज भ्रान्त-एम्प्लायड होते हैं। जनता पार्टी की कमिटिमेंट है कि 10 साल में दूरेक

को रोजगार देंगे। लेकिन कोई फ्रेज प्रोक्लम तो बनाना चाहिए कि एक साल में कितनों को, 2 साल में कितनों को रोजगार देंगे। मैं मानता हूँ कि पहले सप्ताह मशीनरी ज्यादा तेज नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो टारगेट बताइए। श्री सुब्रह्मण्यम जी ने भी 1976 में कहा था कि हम एक साल में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन एक को भी रोजगार नहीं दिया। तो जो आपका कहना है, उसको कैसे पूरा कर रहे हैं और कितना एक साल में पूरा किया, जब तक आप यह नहीं बतायेंगे, तब तक लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि जनता पार्टी इस चीज में विश्वास करती है कि जो वह कहती है, वह करती है और हमने कर के दिखाया भी है। आगे भी मुझे विश्वास है कि 10 साल में हम करेंगे, लेकिन मंत्री महोदय इस चीज को स्पष्ट करें कि हर साल कितने लोगों को वह एम्प्लायमेंट देंगे।

अभी हमारे माननीय मंत्री ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रखी, उसके बारे में तो विचार होना, लेकिन वह एक बहुत बड़ा कदम है कि डिस्पैरिटी दूर हो। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज तक हमेशा कुछ थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट कर के वही 1956 का प्रस्ताव किया गया, लेकिन अब उन्होंने कुछ डेविशन किया है। लेकिन डेविशन प्रस्ताव से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से पता लगेगा और जब तक वह नहीं होना कुछ नहीं हो सकेगा। मुझे आशा है कि जिस तरह के डायनेमिक मंत्री वह हैं, जरूर पूरा कर के वह बताएंगे।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि डिस्पैरिटीज दूर करने के लिए जनता पार्टी को कमिटेमेंट है। जनता पार्टी ने यह कहा है कि जो प्रापर्टी का फण्डामेंटल राइट है वह नहीं रहना चाहिए, वह कानून के अन्तर्गत से होना चाहिए। मैं वह मांग

करता हूँ कि ग्राम प्रापर्टी का फण्डामेंटल राइट रहा तो आज जो 20 करोड़ लोगों को मकान, रोटी और कपड़ा देना है, नहीं दे सकेंगे, संभव नहीं है। अगर किसी का महल है और बराबर में शोपड़ी है तो उस शोपड़ी पर कम से कम छप्पर जरूर डलना चाहिए और जब तक वह छप्पर नहीं पड़ेगा तब तक डिस्पैरिटी दूर नहीं होगी। फण्डामेंटल राइट आफ प्रापर्टी तो खत्म करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसी तो खत्म कर दिया लेकिन गरीबों को कोई लाभ न मिले। उनको भी लाभ मिलना चाहिए।

आपको याद होना कि लेटेस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि बेसिक फ्रीचर्स विधान में रहने चाहिए। उसको यह पालियामेंट बदल नहीं सकती और उस बेसिक फ्रीचर में प्रापर्टी का फण्डामेंटल राइट इन्क्लूड नहीं था। मैं यह मंत्र-कर्म-कर्म कि इस पर विचार होना चाहिए और ग्रामसे सेशन में इस पर विचार और कार्यवाही होनी चाहिए।

राइट टू वर्क को कम-से-कम सरकार प्रिसिपल में तो जरूर मान ले। मैं मानता हूँ कि अभी दिक्कत है, अभी शायद इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकेंगे, आपकी व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। लेकिन एक प्रिसिपल जरूर माना जाना चाहिए कि राइट टू वर्क यानी हरेक आदमी को काम का अधिकार मिलेगा। तभी हम समझेंगे कि जनता पार्टी सही मानों में कुछ करना चाहती है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, वह किसी एक पोलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का स्वत्व नहीं है। केवल गवर्नमेंट के द्वारा यह काम नहीं होगा। चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, और चाहे कितने भी कानून बनाये जायें, लेकिन जब तक जनता जागृत नहीं होगी, जब तक ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलि-

[श्री कंबर लाल गुप्ता]

स्ट्स में यह अनुभूति पैदा नहीं होगी कि हमारे जो भाई भूखों मर रहे हैं, उन के लिए भी हमें कुछ करना है, और कुछ तकलीफ उठा कर भी इस के लिए कुछ काप्टीव्यूशन करना है, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। यह जापति पैदा करने के लिए सरकार को एक राइट टाइम फ्राक एजुकेशन देनी चाहिए। वातप्ट्री भार्गनाइजेसन को भी इस काम में शामिल करना चाहिए, और देश में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिस के जरिये इन दबे-पिसे, मूक लोगों को काम मिले और कम से कम जीवन के एसेंशल फ्राइटम्ब तो मिल सकें।

मैं चाहता हूँ कि इस सवाल पर सरकार विपक्ष से भी बातचीत करे। मैंने बीस करोड़ लोगों के लिए जो स्पेशल टैक्स का सुझाव दिया है, उस के बारे में और दूसरे स्टैप्स के बारे में सब का कोआपरेशन लिया जाये और एक नेशनल कानसेन्स डेबेलप किया जाये कि किस तरह देश भागे बढ़ सकता है, किस तरह डिस्त्रिटीब कम हो सकती है, कैसे एग्जहिबिशन फ्राक रिचनेस खत्म हो सकती है। अगर सब पार्टियों के सहयोग से इस के लिए एक उचित सामाजिक दृष्टिकोण पैदा किया जाये, तो एक दिन जरूर आयेगा, जब महात्मा गांधी का यह सपना साकार होगा कि इस देश में रामराज्य स्थापित हो। अगर डिस्परिटीब कायम रहें, तो प्रजातंत्र भी खत्म हो जायेगा—प्रजातंत्र भी नहीं रहेगा।

MR. CHAIRMAN: Motion moved :

"This House urges upon the Government to take effective steps to improve the economy of the country and to reduce the inequalities of income, wealth and personal consumption."

There are some Amendments to be moved.

SHRI S. S. DAS (Sitamarhi): I beg to move:

That in the resolution,—

add at the end—

"and the loot of the rural people by the urban elite and organised pressure groups be curbed. The House further

directs the Government to basically restructure the outmoded, exploitative and elitist state—capitalist model of the Indian society and the Indian State." (1)

MR. CHAIRMAN: Shri Brij Bhushan Tiwari—not present;

Shri Chandra Shekhar Singh not present.

SHRI GAURI SHANKAR RAI : (Ghazipur) I beg to move:

That in the resolution, —

for "wealth and personal Consumption" substitute—

"Pay, wealth and fix a Ceiling on the expenditure" (4)

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Dhari Shastri—~~not Present~~.

श्री श्याम सुन्दर दास : सभापति महोदय, मैं भावानात्मक स्तर पर श्री कंबर लाल गुप्त के प्रस्ताव के साथ हूँ, लेकिन उस प्रस्ताव में जो फ्राकांशायें व्यक्त की गई हैं, वे ऐसी फ्राकांशायें हैं, जिन के बारे में अभी तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई मतभेद नहीं रहा है। मैं अपने संशोधन के द्वारा उन के प्रस्ताव में कुछ बातें जोड़ देना चाहता हूँ, ताकि सरकार के सामने केवल इतना ही न रहे कि विषमताओं को कम करना है और रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं, बल्कि इस बात का भी विचलेषण किया जाये कि क्या कारण है कि इस के बावजूद कि पिछली सत्तारूढ़ पार्टी इन्हीं लक्ष्यों को मानती रही है, लेकिन पहली पंच-वर्षीय योजना से ले कर आज तक गांव गरीब होते चले गये हैं और हिन्दुस्तान के मानचित्र में कुछ शहर या औद्योगिक केन्द्र सत्ता, सम्पन्नता और वैभव के केन्द्र बन कर रह गये हैं। मार्च, 1977 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, और इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ बातें स्मरण रखनी चाहिए। मेरे कहने का यह आशय नहीं कि सरकार उन चीजों को भूलती जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार हम लोगों ने आशा की थी, सरकार को चूँकि पिछला बजट ऐसे समय में बनाना पड़ा कि सरकार उस के अनुरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकी। इसलिए अभी समय है कि जब कि जनता पार्टी की कार्य समिति ने जो फैसला किया है या हमारे चुनाव घोषणा-पत्र

में जिस तरह के फैसले हैं उन दिशाओं में सरकार को कुछ ठोस बातें करनी चाहिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद जितने देश उपनिवेशवाद के बंगुल से मुक्त हुए उन में हिन्दुस्तान का एक प्रमुख स्थान था। यों रूस की क्रान्ति के बाद वाज्जाप्ता राज्य के द्वारा नियोजनात्मक विकास से राज्य का आर्थिक ढांचा मजबूत किया जा सकता है ऐसी एक कल्पना आई और ऐसी कल्पना जहां तक आर्थिक क्षेत्र है बहुत मामलों में सफल भी हुई। लेकिन जनतांत्रिक ढांचे के अंदर योजना के द्वारा हम देश का आर्थिक विकास करेंगे, बेकारी दूर करेंगे, प्राइसेस का स्तर एक प्रकार का बना रहेगा या विकास की दर के साथ चाहे मूल्य के स्तर में थोड़ी वृद्धि होगी, ऐसी चीज चलाने की बात हुई। लेकिन देश का जो विकास हुआ वह गलत रास्ते पर चला गया। उत्पादन पर, बड़े उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। यह सही है कि अब पहली बार लगता है कि रोजगार को केन्द्र माना जायगा, समता के साथ सम्पन्नता आ सकती है और रोजगार के द्वारा ही उत्पादन बढ़ सकता है, इन सारी बातों को सरकार मानने लगी है। लेकिन अभी तक जो सरकार की आर्थिक नीति है, मैं नहीं जानता कि इंडस्ट्रियल पालिसी की घोषणा होगी तो उस में इन सारी बातों की चर्चा होगी या नहीं होगी लेकिन अभी तक इस तरह का कोई ठोस कार्यक्रम नहीं आया है। जिस तरह से कास्मोपोलिटन सेंटर्स समूचे संसार के पैमाने पर रहे, कुछ मेट्रोपोलिटन कण्ट्रीज रहे जिन्होंने अविकसित देशों को एक्सप्लायट किया एडवर्स ट्रेड के द्वारा, उसी तरह से एक देश के अन्दर भी उसी तरह के अनेक उपनिवेश और कुछ मेट्रोपोलिटन सेंटर्स हैं जो समूचे देश का शोषण करते रहे हैं। माओ-त्से-तुंग ने एक बार यह नारा दिया था कि देहात को अब चाहिए कि वह शहरों की ओर बढ़े और शहरों

को घेर ले। सम्पूर्ण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बैसे देश जो कृषि-प्रधान देश हैं वहां की राजनीति शहरी सभ्यता के साथ, शहरी राजनीति केय केन्द्रित हो गई जहां आर्गनाइज्ड प्रेशर ग्रुप हैं चाहे वह लेबर के हों चाहे बर्जुआ के हों लेकिन देहात में एक झूठे प्रकार के विभाजन की स्थिति वे बार बार पैदा करते रहते हैं ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स में और फार्मर्स में लेकिन जहां प्राइस फिक्सेशन का सवाल आता है ऐग्रीकल्चरल कमोडिटीज की प्राइस और मैन्यूफैक्चर्ड आर्टिकल्स की प्राइस में सामान्यतया देखा गया है कि उत्पादित वस्तुओं का मूल्य जिस स्तर पर एक बार चला जाता है अगर घटता भी है तो .5 परसेंट या .4 परसेंट लेकिन ऐग्रीकल्चरल कमोडिटीज में चाहे वह रा-मैटीरियल हों या सीरियल्स हों उन का प्राइस लेबल बढ़ता है तो फिर उस को आर्टिफिशियली चाहे अमेरिका से अन्न मंगा कर या कनाडा से रशिया से गेहूं और अन्न मंगा कर उस की प्राइस को घटा दिया जाता है। आप देखें शुगर केन का प्राइस एक और शुगर का प्राइस दूसरा है। काटन का प्राइस कम है और काटन टेक्सटाइल का प्राइस ज्यादा है। बिजली आप देते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में उस का रेट बहुत कम रहता है और वही बिजली जब देहात में इरीगेशन के लिए दी जाती है तो उस का रेट बहुत ज्यादा रहता है। तो एक तरह से प्लाण्ड लूट चल रही है रूरल सेक्टर की अर्बन सेक्टर के द्वारा और इसके कारण आज हिन्दुस्तान का मजदूर वर्ग भी दो हिस्सों में बंट गया है— एक तो जो सर्टेन सेंटर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगों के जहां केन्द्र हैं वहां जो आर्गनाइज्ड लेबर है उस को पर डे जितनी मजदूरी मिलती है, उस की तुलना खेतिहर मजदूरों से करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि यहां का जो मजदूर वर्ग है उस मजदूर वर्ग को भी दो हिस्सों में बांट

[श्री श्याम सुन्दर दास]

दिया गया है। और उनका शोषण चलता रहा। भारतीय राजनीति का जो सत्तारूढ़ वर्ग रहा है उसका चस्का रहा है कि मजदूरी के मामले में, जमीन के मामले में या भ्रनेकों दस प्रकार के सवाल उठा कर झगड़ा पैदा करें, भ्रगर मजदूरी और जमीन के मामले में झगड़ा न हो तो जातपंत के नाश पर झगड़ा पैदा किया जाये ताकि देहातों को विभाजित करके रखा जा सके और इस प्रकार से शहरी लोगों का वर्चस्व बराबर बना रहे। इसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दुस्तान का आर्थिक विकास लापसाइडेड हो गया है। यहाँ की राजनीति कुछ मुख्यतः चुनिन्दा वर्गों के हाथ में सिमट कर रह गई है जिन्होंने अपना हित बरकरार रखा है और इस प्रकार से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का शोषण शहरी अर्थ-व्यवस्था के द्वारा होता रहा है। जब तक इसके बारे में अर्थ मंत्री निश्चित रूप से निर्णय नहीं लेंगे तब तक रूल एण्डस्ट्रीज को डेक्लप करना, काटज एण्डस्ट्रीज को डेक्लप करना, इरीगेशन फैसिलिटीज देना सम्भव नहीं हो पायेगा। यह सारी बातें एक नारे तक ही सिमट कर रह जायेंगी और उनका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकार करे और उस पर ईमानदारी के साथ अमल करे।

श्री कैरी शंकर दस (याजीपुर) :
सम्प्रति महोदय, माननीय कंवर लाल जी गुप्त ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें मेरा एक छोटा सा संशोधन है। इसकी अंतिम पंक्ति में है : 'Wealth and personal consumption, उसकी जगह पर जोड़ दिया जाये : 'pay, wealth and fix a ceiling on the expenditure:'

यह बहुत छोटा सा संशोधन है। मैं इस समय यहाँ पर सार्वाधिक प्ररनों की लम्बी विवेचना नहीं करना चाहता क्योंकि प्रस्ताव रखने वाले भाई ने बड़ी व्याख्या कर दी है। मैं चन्द मुद्दों पर थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए इस देश के समाज में ग्रामूलकूल परिवर्तन करने की कल्पना किसी पक्ष की रही है या है। पहले इसकी कुछ चर्चा अवश्य होती रही है लेकिन ग्रामूलकूल परिवर्तन करने की कल्पना कभी नहीं रही है। इस सम्बन्ध में कुछ और अधिक कहने से लाभ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कुछ बातें निश्चित होनी चाहिए। एक तो बिना समाजवाद और ऊंची बातों को कहे हुए इनकम और वेजेज का जो फर्क है उसको कम करना होगा। आज भी उत्तर प्रदेश में एक चौकीदार पांच रुपये पाता है और राष्ट्रपति दस हजार रुपये पाते हैं। इण्डस्ट्रियल हाउसेज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वे राष्ट्रपति से भी ज्यादा पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसी तनख्वाह पाते हैं जिसका रुपये में आप हिसाब नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप तनख्वाहें बांध दें और परक्वोजिट्स बन्द की जायें। आज मंत्री जो तनख्वाह पाते हैं, मैं नहीं कहता कि वह ज्यादा है, आप चौगुनी तनख्वाह कर दीजिए लेकिन यह निश्चय हो जाना चाहिए कि कितनी इनकम है, कितना खर्चा है और कितना इनकम टैक्स है। इसी तरह से बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, पार्लेमेण्ट के मेम्बर हैं उनको सुविधायें मिलती हैं, उनका आप हिसाब लगाइये। गरीब छात्रों को उनके लिए सब जगह पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो सुविधाप्राप्त वर्ग सरकार में बना हुआ है उसको हटना चाहिए और निश्चित रूप से

वेजेज के बीच में एक उचित अन्तर स्थापित किया जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आज ही आप एक और तीन का सम्बन्ध स्थापित करें लेकिन क्या कभी सरकार इस बात को सोचेगी या नहीं? आमदनी और वज्ज में क्या रिलेशंस होंगे, कितने गने होंगे, कम से कम इस बात को सोचना चाहिए। सरकार को इस प्रकार से एक नेशनल वज पालिसी बनानी चाहिए। इण्डस्ट्रियल हाउसेज के जो एम्प्लिक्यूटिव हैं व एक दिन में पांच हजार खर्चा कर देते हैं, राष्ट्रपति भी इस स अधिक खर्च कर सकते हैं और वह खर्चा उचित समझा जाता है। इन सारी बातों को देख कर मिनिमम और मैक्सिमम वेजेज क्या हों, यह निश्चित करना चाहिए। एक सूखी तनख्वाह जिसको नैकेड सैलरी कहा जाता है उसमें कोई सुविधायें नहीं होती है। और एक तरफ तनख्वाह पांच सौ होती है लेकिन उसके बाद वह पांच हजार बनती है और एक जो पांच हजार पाता है उसकी कुल तनख्वाह पांच हजार बैंक में जाती है। तो यह व्हाइट कालर्ड तबका जो है, जिसमें मैं भी हूँ, जो सरकार चलाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर्स हैं वे ऐसा इन्तजाम लगाते हैं कि तनख्वाह छोटी मालूम हो लेकिन उसके साथ सुविधायें ज्यादा हों। देखने में तनख्वाह ज्यादा न लगे।

मैं दोनों पक्षों के लोगों से कहना चाहता हूँ—सामाजिक जीवन में हम बड़े अवश्यों की बात करते हैं, हम एक दूसरे पर चार्ज लगाते हैं। हम उनके ऊपर पिछले तीस सत्रों का चाज लगाते हैं—इस अवधि में जो ढोंग और द्विपात्रिसी हुई है, उस का कोई मुकाबला नहीं होगा। उस समय यदि कोई अवसर पड़ता था तो समझता था कि यहाँ समाज ही बदल गया है, मैं उस समय की आदर्शवादिता की बात नहीं करता, लेकिन यह चाहता हूँ कि देश में एक नेशनल वेज-पालिसी बने,

नग्न वेतन मिले और बिबाउट-पर्सनलिट्स मिले।

मैं एक बुनियादी बात और कहना चाहता हूँ—हम आमदनी पर सीलिंग लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खर्च पर सीलिंग लगाने की बात समझ में नहीं आती है। मैं किसी का नाम लना नहीं चाहता हूँ, किसी को मेलाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने को ही लेकर कहता हूँ—हम पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, 500 रुपया हम को तनख्वाह मिलती है, 500 रुपया और नाम से मिलता है, इस तरह से हम को एक हजार रुपया मिलता है, अगर हमारा खर्च आमदनी से अधिक है तो हम को क्या कहा जाना चाहिये। मैं अपने वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ—वे बहुत अनुभवी अधिकारी भी रहे हैं—क्या आपके पास कोई ऐसा मेकेनिज्म है कि आप एक्स-पेंडिचर पर सीलिंग लगा सकते हैं? आप नम्बर दो के पैसे पर ऐश करने वालों को देख लीजिये—उनके कपड़ों को देखिये—उनके ड्राइंग रूम को देखिये—उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, यह बात समझ में नहीं आती है। आप कोई ऐसा हथियार बनाइये जिससे खर्च को नाप जा सके। आज अपने खर्च का हिसाब तो सब बना लेते हैं, दूसरों को एक्यूज करते हैं, लेकिन ठीक से झाँका जाये, तो गुनाह सब के हिस्से में पड़ता है। इस लिये इस पर ईमानदारी के साथ सोचना चाहिये।

एक बात की चर्चा पहले भी बहुत हो चुकी है—पिछले दस सत्रों में हमारे जितने मोनेपोली हाउसेज हैं, वे बहुत ज्यादा बढ़े हैं। वे पिछले 30 सत्रों में उठना नहीं बढ़े, जितना मोनेपोली कमीशन की रिपोर्ट करने के बाद बढ़े हैं। पिछले शांभ सत्रों में तो उन की हैसियत बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। आज पुरानी बातों को छोड़ कर इस दृष्टि से देखा जाना चाहिये कि इस को कैसे रोका जा सकता है, हमारा जो प्रापरेषन बन करीका है,

[श्री गौरी शंकर राय]

काम करने का तरीका है, उस को बदलने की आवश्यकता है ।

इतना बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, लेकिन समय की बहुत कमी है। कोई नई बात कहने का समय ही नहीं है, इस लिये मैं इतना ही कहूंगा कि नेशनल-वेज-पालिसी, खर्च की सीमा और वेतन के साथ बाहरी सुविधाओं को हटा कर, नंगा वेतन देने की व्यवस्था होनी चाहिये। चाहे पब्लिक सैक्टर हो या प्राइवेट सैक्टर हो—सब के वेतन को समान रूप से देखा जाये। आज भार्गनाइज्ड सैक्टर में, जैसे इंश्योरेंस मुलाजिम हैं, वे अपने हक के लिये लड़ सकते हैं, ह्वाइट कालर्ड हैं, हमारे क्यालार रवि भी उन के सवाल को उठा देंगे, स्टीफन साहब भी उठा देंगे और यदि हमारे पास आयेंगे तो हम भी उठा देंगे लेकिन आज जो दबा हुआ तबका है, उस की बात करने वाला कोई नहीं है, उस के लिये लड़ाई नहीं हो पाती है, इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ—हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये, बज्जानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये ताकि देश में नेशनल वेज पालिसी हो, मॅकसिमम और 'मिनिमम रिजेशन खर्च' में हो और नंगा वेतन देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मान्य-वर, श्री कंवर लाल गुप्ता जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उस का पूरा समर्थन करता हूँ। आज हमारे देश में जहाँ आय के अन्तर बहुत बड़ा अन्तर दिखाई देता है, वहाँ खर्च और पूंजी में भी बहुत अन्तर पाया जाता है और हमारी जो आज की प्रक्रिया है, जिस के अधीन हम समाज को नियंत्रित करना चाहते हैं, उस में हर धनवान् आदमी प्रतिदिन अधिक धनी होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है।

हमारे देश के करोड़ों लोग आज ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें कि उन को सही ढंग से भोजन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, पड़ाई का कोई सवाल नहीं, भ्रौषधि की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने के लिये कोई मकान नहीं है। देश में ऐसे लोग भी हैं जिनकी पूंजी आज की पूंजी के समय में सौ करोड़ से नीचे थी आज उन की पूंजी बड़ कर हजारों करोड़ तक पहुँच गई है, जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था चल रही हो वहाँ पर किसी हालत में समाज में शान्ति नहीं रह सकती है। इस प्रकार से अन्तर यहाँ कायम रहेगा तो इस में सन्देह नहीं है कि देश में लोकतन्त्र भी खतरे में पड़ सकता है। जहाँ आज हम सामाजिक समानता अथवा राजनीतिक समानता की बात करते हैं वहाँ पर आर्थिक समानता के बारे में भी हमें सोचना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को उस की आवश्यकता के अनुरूप सही साधन मिलने चाहियें, धन मिलना चाहिये। ऐसी व्यवस्था नहीं रहनी चाहिये जहाँ करोड़पति अरबपति बन जायें और गरीब जिस के पास पाँच रुपये हैं उस का वह रुपया भी समाप्त हो जाए, वह अपनी जीवन की आवश्यक वस्तुओं को भी खरीद न सके, अपने जीवन को सही ढंग से न चला सके। जहाँ आय पर सीमा लगाएं वहाँ एक्सपेंडीचर अर्थात् खर्च पर भी सीलिंग आय लगाएं। उन के साथ-साथ कैपिटल पर भी लगाएं। अनियंत्रित पूंजी हमेशा ही देश के लिये घातक होगी। बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जिन के पास साधन होंगे उन के पास ही उस अवस्था में पूंजी एकत्रित हो जाएगी और वे पूरे समाज को पूंजी के बल पर अपने दबाव में रखेंगे। आज की स्थिति ऐसी ही है। आज हमारे देश में प्रशासन तथा पूरा अखबार का जो तंत्र है जिसे स्टेट आफ जर्नलिज्म कहते हैं यह सभी उन के कब्जे में चला आ रहा है। यह जो स्थिति है अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे देश में लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है।

मौलिक अधिकार के रूप में सम्पत्ति के अधिकार का मैं विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता कि सम्पत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना रहे। इस के मौलिक अधिकार बने रहने के कारण हमारे देश में गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। ऐसे लोगों का हो रहा है जो आर्थिक विपन्नता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

माननीय कंवर लाल गुप्त जी के प्रस्ताव का मैं इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जहाँ आय पर एक सीमा लगाई जाये वहाँ खर्च और पूँजी पर भी सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): Sir, the motion that has been moved reads as follows:

"This House urges upon the Government to take effective steps to improve the economy of the country and to reduce the inequalities of income, wealth and personal consumption."

I don't think there should be any difference of opinion in regard to the second part of this resolution, to reduce the inequalities of income, wealth and personal consumption. And, I presume, the reference to the economy of the country means that we should develop the economy in such a way that these objectives, that is, reducing inequalities of income, wealth and personal consumption, are achieved.

I can only say that the steps which we are taking to improve the economy are many, and in fact, I think, we are achieving a measure of success.

Ever since the Government assumed office, it has been making every effort to improve the economy in order to achieve the basic aims of the policy to which it is committed, namely the elimination of poverty and destitution and establishment of a social order which assures freedom and equality to all its citizens. But the dimensions of the problems of poverty in India and complexity of the factors underlying them, rule out any quick or easy solution. Failure of over two decades of planning to make any dent on poverty show that if the problem is to be tackled effectively, the entire strategy of the development should be reviewed and priorities re-defined and the economic policy will need to be reformulated in the light of the new strategy and priorities.

While in the short run the exigencies of the current situation is to be taken into account, the basic thrust of the economic policy both for the short as well as the long-term will depend on the approach one adopts to the strategy of development.

We have initiated steps already to re-define the priorities conforming with the new strategy of the planning. While the Fifth Plan for 1978 to 1983 is still being formulated by the reconstituted Planning Commission.... (Interruptions).

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Minister should tell us specifically the steps taken and not the policy which they frame.

MR. CHAIRMAN: Allow him to proceed.

श्री रामानन्द तिवारी (बक्सर) :

अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह जानना चाहते हैं, 20, 30 वर्ष का कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जनता पार्टी की सरकार 9 महीने से क्या कर रही है, और भागे क्या करेगी गरीबी को दूर करने के लिए? उपदेश सुनने के लिए हम यहाँ नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि गरीबी को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है?

SHRI H. M. PATEL: Mr. Chairman, I regret that what the hon. Members desire cannot be achieved with the speed with which they desire. They ask what have we been doing. We have been doing many things. (Interruptions). Please keep patience and then you may learn something. If you do not have patience you cannot learn. What I am pointing out are facts. You have mismanaged the economy of this country for thirty years. You cannot expect us to change things overnight. It takes time.

15'02 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

Let us understand this. After all, I should have thought the hon. Members will realise this. The guidelines have been issued by the Planning Commission for the preparation of the State Plans for 1978-79 bearing in mind our basic objectives of accelerating the growth of per capita income to the maximum possible extent and to progress towards self-reliance. That is what is happening. We have to recognise that to tackle the problem of

[Shri H. M. Patel]

poverty, rooting out the problem of unemployment and underemployment, we have to emphasise the need to promote measures which would help to provide employment to a larger number of people. It has been pointed out in the guidelines that in order to attain the contemplated employment targets, taking into account the anticipated rise in the labour force, it will be necessary to ensure significant and sustained increase in the labour absorption in productive work in agriculture including processing, storage, transport and distribution.....

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Ten minutes should be given to the Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER: At 4 O' clock we have to take up the Adjournment Motion.

SHRI H. M. PATEL: Guidelines have to be formulated in order to achieve a substantial shift in the investment target and the Central and State Governments Policies in areas of the economic policy will need to be coordinated with the Plan priorities. Since assured water supply is crucial for increasing productivity of agriculture and creation of employment, highest priority has to be given to investment in irrigation than it has been receiving so far. Funds would have to be pre-empted for investment in irrigation and agricultural production before allocations are made to other sectors. It is intended to bring an additional 17 million hectares of land under irrigation in the next five years. Large outlays would be needed to increase per generation keeping in view the potential for employment generation.

16.00 hrs.

श्री राधानाथ तिवारी : इनकम पर घोषा निर्धारित कोबिएगा कि नहीं ? यह क्लिने दिनों में, कम-से-कम और अधिक से अधिक, क्या कीजिएगा ?

SHRI H. M. PATEL: Hon. Members are getting impatient but they must know that we have appointed a study group on this question of wages and incomes policy with a view to evolve a national wage policy, which I think the mover of this resolution desired. The necessity for appointing such a study group arose because many distortions had come into the economy; in the organised labour for instance, there are groups at high levels of wages; there are others who are at the medium level.

MR. DEPUTY-SPEAKER: According to our rules, we have to take up the adjournment motion.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will you abolish the fundamental rights to property? ... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: We take up other business. Shri Samar Guha.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I beg to move :

"That the further discussion on the resolution regarding steps to improve the economy and reducing inequalities of income, etc. moved by Shri Kanwar Lal Gupta on the 9th December, 1977, be adjourned to the next day allotted to the Private Members' Resolutions in the next session and the provisions of sub-rule (1) of Rule 30 and the proviso to Rule 29 be suspended in their application to this resolution to enable the resolution to be set down in the List of Business without ballot, as the first item therein."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

"That the further discussion on the resolution regarding steps to improve the economy and reducing inequalities of income etc., moved by Shri Kanwar Lal Gupta on the 9th December, 1977, be adjourned to the next day allotted to the Private Member's Resolutions in the next session and the provisions of sub-rule (1) of Rule 30 and the proviso to Rule 29 be suspended in their application to this resolution to enable the resolution to be set down in the List of Business without ballot, as the first item therein."

The motion was adopted

16.03 hrs.

RESOLUTION RE, REPEAL OF CONSTITUTION (FORTY-SECOND AMENDMENT) ACT AND WITHDRAWAL OF MISA

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I beg to move :

"This house recommends to the Government to redeem its sacred pledge, made to the people on the historic occasion of the last Lok Sabha Election, by forthwith repealing the Constitution (Forty-second Amendment) Act, which was passed by Parliament under a